



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 2004/फाल्गुन 2, 1925

No. 35]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 21, 2004/PHALGUNA 2, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 17 फरवरी, 2004

सं. टीएमपी/5/2004-एनएमपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा जेट्टी संख्या 10 और 11 में प्रहस्तित कार्गो के लिए वर्ष 2003-2004 हेतु तदर्थ बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएमपी/5/2004-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)

.....

आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2004 के 11वें दिन पारित)

यह प्रकरण मेंगलूर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) के लिए दी गई जेट्टी सं. 10 और 11 में प्रहस्तित कार्गो के लिए वर्ष 2003-04 हेतु तदर्थ बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। एनएमपीटी ने इस प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बातें कही हैं :

- (i) वर्ष 2003-04 के लिए तदर्थ दर की गणना चालू वर्ष के दौरान नौ महीनों के प्रचालन की वास्तविक आय के आधार पर की गई है। तदर्थ दर निर्धारित करने के लिए एमआरपीएल द्वारा अभिव्यक्त टनभार पर विचार किया गया है।
- (ii) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमे में पत्तन के अधिकार और दावे के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना तदर्थ दर की गणना करने में ऋण वापसी की राशि के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इस विषय में प्राधिकरण के निदेशों का पालन किया गया है।
- (iii) प्रस्तावित तदर्थ दर की विस्तृत गणना प्रस्तुत की गई है। एनएमपीटी ने जेट्टी सं. 10 और 11 हेतु वर्ष 2002-03 के लिए अनुमोदित, रु. 71/- प्रति मी.ट. की तदर्थ दर के समक्ष वर्ष 2003-04 के लिए रु. 63/- प्रति मी.ट. की तदर्थ दर का प्रस्ताव रखा है।
- (iv) एमआरपीएल ने वार्षिक लेखों के आधार पर वर्ष के अंत में अंतिम समायोजन किए जाने की शर्त के अधीन प्रस्तावित तदर्थ दर को दी गई अपनी स्वीकृति की पुष्टि की है। एमआरपीएल ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की है कि उसके द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य लंबित मुद्दों पर अंतिम दरें निर्धारित करने के समय ध्यान दिया जा सकता है और दरे लंबित मुकदमों के फैसले के आधार पर परिवर्तनीय हैं।

1.2. पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच हुए पारस्परिक समझौते के मद्देनजर, एनएमपीटी ने इस प्राधिकरण से वर्ष 2003-04 के लिए रु. 63/- प्रति मी.ट. की बंदरगाह शुल्क दर अनुमोदित करने का अनुरोध किया है।

2. साथ ही साथ, हमें एमआरपीएल से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने वर्ष 2003-04 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 में प्रहस्तित कार्गो के लिए रु. 63/- प्रति मी.ट. की प्रस्तावित तदर्थ बंदरगाह शुल्क दर स्वीकार करने के लिए एनएमपीटी को दी गई अपनी सहमति की पुष्टि की है।
- 3.1. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एमआरपीएल ने, इस प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई, 2000 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसने मुख्य रूप से एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों पर निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) देने के मुद्दे को चुनौती दी है।
- 3.2. एनएमपीटी द्वारा, बंदरगाह शुल्क दर की गणना में तीन विशिष्ट मुद्दों, यथा पोत संबंधी आय क्रेडिट बैंक करना, एस्क्रो खाता ब्याज को क्रेडिट बैंक करना और ऋण वापसी के मूल्यह्रास को क्रेडिट बैंक करना पर दायर समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले, इस प्राधिकरण द्वारा 21 मार्च, 2002 को पारित आदेश की समीक्षा के लिए एनएमपीटी ने भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है।
- 3.3. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एमआरपीएल द्वारा दायर रिट याचिका केवल वर्ष 1996—2000 अवधि के विषय में है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एनएमपीटी को अनुवर्ती अवधि के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है।
4. चूंकि वर्ष 2003-04 हेतु दोनों जेट्टियों सं. 10 और 11 के लिए रु. 63/- प्रति मी.ट. की प्रस्तावित तदर्थ बंदरगाह शुल्क दर पर दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति हो चुकी है और यह इस तथ्य को भी स्वीकार करती है कि अंतिम दर निर्धारित होने तक केवल यही दर अंतरिम दर के रूप में कार्य करेगी, इसलिए यह प्राधिकरण लागत व्यौरों का विस्तृत विश्लेषण किए बिना प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।
5. यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1996-97 से 2001-02 के लिए जेट्टी सं. 10 की अंतिम बंदरगाह शुल्क दरों का निर्धारण अभी तक लंबित है। एनएमपीटी को एमआरपीएल के साथ विचार-विमर्श करके एक उपयुक्त प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2003 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जा चुकी है। एनएमपीटी ने संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है। एनएमपीटी को पुनः सलाह दी जाती है कि वह वर्ष 1996-97 से 2001-2002 के लिए जेट्टी सं. 10 हेतु बंदरगाह शुल्क दर के निर्धारण के लिए सहमतियुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस प्रस्ताव में वर्ष 2002-03 के लिए जेट्टी सं. 10 और 11 की अंतिम बंदरगाह शुल्क दरें भी शामिल की जा सकती हैं।
6. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण वास्तविक और स्वीकार्य लागतों पर आधारित अंतिम बंदरगाह शुल्क प्रभावों का निर्धारण होने तक एनएमपीटी में जेट्टी सं. 10 और 11 में वर्ष 2003-04 के दौरान प्रहस्तित कार्गो पर रु. 63/- प्रति मी.ट. की तदर्थ बंदरगाह शुल्क दर अनुमोदित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th February, 2004

No. TAMP/5/2004-NMPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the New Mangalore Port Trust for fixation of *ad hoc* wharfage rate for the cargo handled at oil Jetties No. 10 and 11 for the year 2003-2004 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/5/2004-NMPT

The New Mangalore Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 11th day of February, 2004)

This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of *ad hoc* wharfage rate for the year 2003-04 for the cargo handled at Jetties No. 10 and 11 dedicated for the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL). The NMPT has made the following main points in the proposal:

- (i) Calculation of *ad hoc* rate for the year 2003-04 is done taking into account the income at actuals for nine months of operation during the current year. Tonnage as projected by the MRPL has been considered for fixation of the *ad hoc* rate.
- (ii) The direction of the TAMP about treatment of loan repayment amount has been complied with in the computation of the *ad hoc* rate without prejudice to the right and contentions of the port in the litigation pending before the Hon'ble High Court of Karnataka.
- (iii) Detailed calculation of the proposed *ad hoc* rate is furnished. The NMPT has proposed an *ad hoc* rate of Rs. 63/- PMT for Jetties No. 10 and 11 for the year 2003-04 as against the *ad hoc* rate of Rs. 71/- PMT approved for the year 2002-03.

- (iv) The MRPL has confirmed its acceptance to the proposed *ad hoc* subject to final adjustment based on Annual Accounts at the year end. The MRPL has also agreed that various other pending issues raised by it can be addressed at the time of fixing the final rates and the rates are subject to change depending on the outcome of pending litigations.
- 1.2. In view of the mutual agreement between the port and the user, the NMPT has requested this Authority to approve the *ad hoc* wharfage rate of Rs. 63/- PMT for the year 2003-04.
2. Simultaneously, we received a communication from the MRPL confirming its consent given to the NMPT for accepting the proposed *ad hoc* wharfage rate of Rs. 63/- PMT for cargo handled at Jetties Nos. 10 and 11 for the year 2003-04.
- 3.1. It may be relevant to mention that the MRPL has filed a Writ Petition in the High Court of Karnataka against the Order passed by this Authority on 19 July, 2000. It has mainly challenged the issue of allowing Return on Investment (ROI) on the NMPT assets.
- 3.2. The NMPT has also filed Writ Petitions in the Hon'ble High Court of Karnataka for a review of the Authority's Orders passed on 21 March, 2002 rejecting the review petitions filed by the NMPT on three specific issues viz. credit back of vessel related income, credit back of escrow account interest and credit back of depreciation of repayment of loan in the computation of the wharfage rate.
- 3.3. It may be relevant to mention that the Writ Petition filed by the MRPL is only about the period 1996—2000. The Hon'ble High Court of Karnataka has allowed the liberty to the NMPT to fix wharfage rate in accordance with the MOU for the subsequent period.
4. Since the proposed *ad hoc* wharfage rate of Rs. 63/- PMT for both the Jetties Nos. 10 and 11 for the year 2003-04 is mutually agreed between both the parties and also recognising the fact that such a rate is only going to serve as an interim rate subject to fixation of final rate, this Authority is inclined to approve the proposal without resorting to an elaborate analysis of the cost details.
5. It is to be noted that fixation of final wharfage rates for Jetty No. 10 for the years 1996-97 to 2001-02 is still pending. The NMPT has already been advised to submit, in consultation with the MRPL a suitable proposal by 30 November, 2003. The NMPT has not submitted the revised proposal so far. The NMPT is again advised to file an agreed proposal for fixation of wharfage rate for Jetty No. 10 for the years 1996-97 to 2001-02. This proposal can also include final wharfage rates for Jetties Nos. 10 and 11 for the year 2002-03.
6. In the result, and for the reasons given above, this Authority approves an *ad hoc* wharfage rate of Rs. 63/- PMT on cargo handled during the year 2003-04 at Jetties Nos. 10 and 11 at the NMPT subject to determination of final wharfage charges based on actual and admissible costs.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/143/03-Exty.]